www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-4* *April 2025***

आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद

डॉ0 कंचन कुमारी

पी–एच0 डी0, राजनीति विज्ञान विभाग, बी0एन0एम0यू0, मधेपुरा

सारांश–

नक्सलवाद या माओवाद का भारतीय संदर्भ में एक ही अर्थ है। भारतीय सरकार द्वारा उग्रवादी वामपंथियों को ही नक्सलवाद की नक्सलवादियों की संज्ञा दी गई है। 80 के दशक के मध्य में कुछ संगठनों का पिछले इलाकों में गठन किया गया। जैसे– आंध्र प्रदेश में पीपुल वार ग्रुप, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में माओवादी समन्वय समिति। 90 के दशक में माओवादी गतिविधियों का विस्तार तेजी से अल्पविकसित एवं जनजाति क्षेत्रों में हुआ। सितंबर 2004 में दो संगठनों पी0डब्ल्यू0जी0 एवं एम०सी०सी० ने आपस में विलय कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नाम से नए संगठन को जन्म दिया गया। परिणाम स्वरुप यह राज्यों के लिए कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया। जिसके कारण देश में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला दुर्भाग्य से वे सभी कारण आज भी मौजूद हैं। समाज में व्याप्त वर्ग भेद के साथ गरीबी एवं बेरोजगारी भी एक प्रमुख कारण है।

कुँजी– आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद,माओवाद, सरकार, चुनौती।

प्रस्तावना–

हमारे देश के सामने पिछले 6 दशक से एक गंभीर समस्या बनी हुई है जिसका कारण नक्सलवाद है। 70 के दशक में नक्सलवाद ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया था । यह समस्या नेपाल की तराई से लेकर बिहार, प0 बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि प्रदेशों से होते हुए कर्नाटक तक पहुँच गया है, जो देश का लगभग 40 प्रतिशत भू–भाग है ।

नक्सलवाद की समस्या देश का आंतरिक मामला है इसलिए सभी राज्यों का यह दायित्व बनता है कि इसके समाधान को लेकर आगे आएँ। क्योंकि इतनी बड़ी जमात और उनकी माँगों की अनदेखी नहीं की जा सकती। केन्द्र सरकार जब भी कोई योजना बनाती है तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हाशिये पर रखे गए एक – एक व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँच सके, क्योंकि इस समस्या के जड़ में शोषण और असमानता ही है।

नक्सली आन्दोलन पर वैचारिक प्रभाव– नक्सली आन्दोलन की प्रेरणा भले ही चीन से मिली हो लेकिन देश की सामाजिक, आर्थिक विषमताओं ने इस आन्दोलन के विकास के लिए भरपूर खाद–पानी दिया। हम यह जानते हैं कि हर वाद किसी–न–किसी विचारधारा पर आधारित होता है और हर वाद के कोई–न–कोई पुरोधा जरूर होते हैं। उदाहरणस्वरूप– समाजवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद, गाँधीवाद, लोहियावाद इत्यादि से हम वाकिफ हैं।

दरअसल माओ के महान प्रशंसक चारू मजमूदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में विद्रोह उस समय उग्र हो गया जब न्यायालीय आदेश के बावजूद एक किसान को खेत जोतने का वाजिब हक देने के बजाए जमींदारों के गुंडों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। माओवादी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सलवाड़ी से प्रारम्भ यह आन्दोलन मूलतः शोषण, अन्याय, गरीबी, असमानता आदि के परिणामस्वरूप ऊपजी एवं यह अपनी प्रकृति

में नैतिक, ईमानदार, गरीबों एवं वंचितों के लिए लड़ने वाले लोगों का समूह है, जो लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप में विश्वास नहीं करते तथा इसे ध्वस्त कर एक नवीन समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं।

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा वातावरण के आकलन के समय उसकी आंतरिक स्थिति का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक होता है। दरअसल आंतरिक स्थितियां सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। जे बंधोपाध्याय ने आंतरिक सुरक्षा के संबंध में दो परिभाषाओं को प्रतिपादित किया है–

पहली परिभाषा आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य किसी संविधान विशेष अथवा शासन विशेष शासन अनुरूप जिसकी भी किसी भी हिंसात्मक आंतरिक विरोध से सुरक्षा की जानी है। दूसरी परिभाषा के अनुसार आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य राज्य की स्थिरता जीवन क्षमता और स्थायित्व का स्वयं के अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व से है जिसकी उन हिंसात्मक रूप से अराजक अथवा अव्यवस्थित ताकतों से रक्षा की जानी है जो कि अंदर से ही प्रत्यक्ष रूप से उसके अस्तित्व को खतरे में डालती है जिससे कि वह वाहे आक्रमण अथवा प्रभुत्व का आसान शिकार बन जाए।

इस शोध लेख में भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों का आकलन दूसरी परिभाषा के आलोक में किया जाएगा। कब कहां क्या और कौन सी विनाशकारी घटना घटित हो जाएगी यह कहा नहीं जा सकता। भारत के गृह मंत्रालय से प्राप्त तथ्यों के अनुसार देश के 535 जिलों में से 200 जिले सशस्त्र विद्रोह आतंकवादी गतिविधियों जातिवादी और नक्सली शत्रुता एवं संघर्ष के चंगुल में है। क्योंकि इस शोध लेख का केंद्र बिंदु नक्सलवाद है तो आइए इसी पर चर्चा केंद्रित करते हैं। शोध लेख का शीर्षक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने वर्ष 2010 में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित संबोधित करते हुए कहा था कि नक्सल आंदोलन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है।

नक्सलवाद या माओवाद का भारतीय संदर्भ में एक ही अर्थ है । भारतीय सरकार द्वारा उग्रवादी वामपंथियों को ही नक्सलवाद की नक्सलवादियों की संज्ञा दी गई है। नक्सलवाद की समस्या का आरंभ पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से कानू सान्याल व चारू मजूमदार के नेतृत्व में मार्च 1967 में प्रारंभ हुआ धीरे–धीरे यह आंदोलन बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य तक पहुंच गया देश के लगभग एक तिहाई हिस्से पर देश भर में भारतीय कानून व्यवस्था को नक्सलवादी आंदोलन ने चुनौती पेश की है। लाल गलियारे के नाम से प्रसिद्ध लगभग 56000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नक्सलियों नक्सलियों को चढ़ावा दिए बगैर कोई भी व्यापार या उद्योग नहीं चलता। इसके अलावा कर्नाटक तमिलनाडु केरल मिजोरम मणिपुर असम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी यह माओवादी सकरी हुए हैं। 2009 में गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि खुफिया सूचना के मुताबिक दिल्ली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी नक्सली हिंसा के सबूत मिले हैं।

प्रारंभ में नक्सलवादियों का उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक समानता को स्थापित करना था इन्हीं विचारों का उपयोग करते हुए नक्सलवादी नेता चारु मजूमदार ने घोषणा की थी कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। माओवादी विचारधारा से प्रेरणा लेने वाले नक्सलवादी पार्टी के गठन के 2 साल बाद तक वह बहुत चर्चा में रहे नक्सलवादी आंदोलन शुरू शुरू में दूर गांव तक फैल चुका था देश के तमाम हिस्सों में पहुंच चुका था सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य गोवा पांडिचेरी और अंडमान निकोबार दीप अकेला के से अछूते रहे। इस आंदोलन के नेता चारु मजूमदार का अनुमान था कि भारत का हर कोना एक ज्वालामुखी बन चुका है। यह फूटने वाला ही था और भारत में बहुत ज्यादा उथल–पुथल की संभावना थी पूर्णविराम यही ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सदस्यों का आह्वान किया था उनका संदेश था कि संघर्ष कहीं भी और हर जगह विस्तार करो। उसके सशस्त्र संघर्ष के अतिरिक्त आमजन के बीच अपने को ऊंचा उठाने का कार्य किया कालांतर में उसने छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी आजाद निर्माण कार्य आरंभ कर दिया था और उसे बाद में सफलता भी मिली थी।

नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि एक यह समस्या है मानव व्यवहार की इसकी जड़ें अन्याय बोध की भावना से जुड़ी हुई है नक्सली समस्या के पीछे गहरी सामाजिक आर्थिक समानता है छिपी हैं अब तक केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को कानून व्यवस्था का मामला मानकर हल करने का प्रयास किया था यही कारण रहा कि लगभग के दशक बीत तमाम दशक बीत के बाद भी यह समस्या जस की

तस बनी हुई है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नक्सलवाद देश के लिए एक गंभी चुनौती है। समस्या के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर वर्षों से प्रयास जारी है। अनेक नीतियाँ बनाई गई किन्तु उन नीतियों का कार्यान्वयन उचित ढंग से आज तक नहीं हो पाया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि 'नक्सलवाद' के मूल में जाकर समस्या के समाधान के लिए समुचित प्रयास किये जायें। गुमराह व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाये। भूमि सुधार कार्यक्रम लागू कर समस्य का स्थायी समाधान किया जा सकता है। नक्सलवाद देश की आंतरिक समस्या है प्रयास के साथ–साथ आमजन का भी यह दायित्व बनता है कि नक्सली समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें नक्सली गतिविधियों में संलिप्त लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर समस्या का समाधान संभव है। यहाँ एक बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि देश में व्याप्त असमानता की खाई को पाटकर इस गंभीर समस्या का निदान किया जा सकता है।

निष्कर्ष–

नक्सलवाद को पनपने एवं पोषण देने में जिन तत्त्वों की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है उसमें गरीबी, बेरोजगारी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, एक बड़े वर्ग के समुचित विकास का अभाव, विस्थापन की समस्या आदि प्रमुख कारण है। इसमें कतई संदेह नहीं है कि नक्सलवाद देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। 1967 से आरंभ हुए नक्सलवादी आंदोलन अपने आरंभिक काल से 53 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है। इस लम्बी अवधि में भी न तो नक्सलवाद का प्रयोजन पूरा हो सका और न ही इसका समाधान हो सका। हाँ, नक्सलवादी विचारधारा एवं सरकारी प्रयासों में अंतर अवश्य दृष्टिगोचर हुए हैं एक विचारधारा के रूप में विद्यमान 'नक्सलवाद' आज भी जीवित है। उसने अपना रूप अवश्य बदल लिया है। भूमिहीन किसान, मजदूरों का सामंतों के विरुद्ध प्रारंभ किये गये आंदोलन आज सरकार एवं सुरक्षा बलों के विरुद्ध आंदोलन बनकर रह गया है। नक्सलियों द्वारा समानांतर सरकार का गठन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि नक्सलियों का संविधान से विश्वास उठ सा गया है। यह देश के लिए गंभीर समस्या है। आवश्यकता इस बात की है कि नक्सली गतिविधि में संलिप्त लोग एवं सरकारी महकमा आमने–सामने बैठकर समस्या का स्थायी समाधान निकालें। यही वक्त की माँग है। सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए यह आवश्यक है।

आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी नीतियाँ इस ढंग से बनायी जाये जिससे आमजन को लाभ पहुँच सके। गरीबी–अमीरी की खाई को पाटकर उन असंख्य लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्रदान कर नक्सलवाद का समाधान किया जा सकता है।

एक तरफ जहाँ इस समस्या की वजह आर्थिक और सामाजिक विषमता समझी जाती रही है, वहीं दूसरी ओर इसे अब एक राजनीतिक समस्या भी समझा जाने लगा है। यही कारण है कि जानकारों की नज़रों में नक्सलवाद सियासी दलों की एक 'चुनावी चक्की' है जिस पर मौका मिलते ही आटा पीसने की कोशिश की जाती है। ऐसा इसलिये भी कहा जाता है क्योंकि, हमारी सरकारें लगातार संविधान की पाँचवीं अनुसूची को तरजीह देने से कतराती रही । गौरतलब है कि इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मामले आते हैं। पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की गई। दरअसल, इन क्षेत्रों में सलाहकार परिषद एक तरह की पंचायत है जो आदिवासियों को अपने क्षेत्रों में प्रशासन करने का अधिकार देती है। इस कौंसिल में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं जिनके तीन–चौथाई सदस्य वे होते हैं जो संबंधित राज्य की विधान सभा में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि हिंसा से प्राप्त की हुई व्यवस्था ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती और अंततः टूट जाती है। दूसरी ओर सरकार को भी कानून–व्यवस्था की समस्या से ऊपर उठकर इनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करने के प्रयास करने चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. जे0 बंधोपाध्याय, द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 9–10
2. नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 7 फरवरी 2010, मुख्य पृष्ठ
3. कुमार, संजय, संपादित, भारत की आंतरिक सुरक्षाः मुद्दे और चुनौतियां, सनराइज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 81–82

4. नेगी, डॉक्टर अवतार सिंह, नक्सलवादः आंतरिक शासन को चुनौती देती एक समस्या, तुणीर, गोरखपुर, वर्ष–3, अंक 7, 15 अगस्त 2006, पृष्ठ– 52
5. योजना, भारत सरकार, मार्च 2006, पृष्ठ 26
6. इंडिया टुडे, मार्च 2007, पृष्ठ 2003
7. आउटलुक, कवरस्टोरी, नक्सलवादः एक हिंसात्मक विचार, जून 2010, पृष्ठ 75

Cite this Article-

'डॉ0 कंचन कुमारी', *'आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद'*, Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:04, April 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i4006

Published Date- 10 April 2025